भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग

****

मासिक मंत्रि मंडल सारांश जुलाई-2021

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां:

(i) कोविड-19 के समाधान के लिए डीबीटी द्वारा किए गए उपाय

क. मिशन कोविड सुरक्षा

भारतीय कोविड वैक्सीन विकास में तेजी लाने और वैक्सीन निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम (पीएसयू) बीआईआरएसी द्वारा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत 5 वैक्सीन कैंडीडेट्स, 19 नैदानिक परीक्षण साइट, प्रतिरक्षाजनकता जांच और पशु मॉडल चुनौती की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 सुविधाओं का समर्थन किया जा रहा है। कोवैक्सीन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 03 उपक्रमों (पीएसयू) और एक निजी क्षेत्र में क्षमता सुविधाओं में वृद्धि के लिए समर्थन दिया जा रहा है।

भारत बायोटेक से सार्वजनिक क्षेत्र के 03 उपक्रमों और गुजरात कोविड वैक्सीन कंसोर्टियम (जीसीवीसी) को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो रहा है और उसकी साप्ताहिक/ आवश्यकतानुसार निगरानी की जा रही है। बीबीआईएल के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता ज्ञापन पर सभी अनुदान प्राप्तकर्ताओं और जीसीवीसी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं; टर्म शीट को अंतिम रूप दे दिया गया है; हाफकाइन बायोफार्मास्युटिकल्स और भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बिबकॉल) के लिए सुविधा डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। आईआईएल परीक्षण के अंतिम चरण में है और तीसरे परीक्षण बैच का सत्यापन चल रहा है।

विभाग ने 1 जुलाई, 2021 को बीआईआरएसी में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दल के साथ बैठक में भाग लिया, ताकि कोवैक्सिन के बड़े स्तर पर उत्पादन तकनीक को स्थानांतरित करने और सुविधा डिजाइन समीक्षा, डीएस निर्माताओं के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं उत्पादन लाइसेंस के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पीएसयू में सामंजस्यपूर्ण नियामक रणनीति पर चर्चा की जा सके।

ख. क्षेत्रीय वैक्सीन सलाहकार समूह (आरवीएजी)

विभाग ने 1 जुलाई, 2021 को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा गठित क्षेत्रीय वैक्सीन सलाहकार समूह (आरवीएजी) की उद्घाटन बैठक में भाग लिया, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव, डीबीटी ने की, यह बैठक विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) को कोविड-19 वैक्सीन से सुरक्षा और प्रभावशीलता पर सलाह देने और एडीबी के वित्तीय निर्णयों के बारे में सूचना देने के लिए आयोजित की गई थी।

ग. भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएससीओजी)

भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएससीओजी) डीबीटी, डीएसटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीएसआईआर, शिक्षा मंत्रालय, आईसीएमआर और राज्य सरकारों की 28 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं का एक संघ है जिसे एक अंतर-मंत्रालयी पहल के रूप में पूरे देश में सार्स-कोव-2 वायरस के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का विस्तार करने, वायरस कैसे फैलता है एवं विकसित होता है, को समझाने के समग्र उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था।

अब तक, आईएनएसएसीओजी ने 58,240 सार्स-कोव-2 जीनोम अनुक्रमित किए हैं। इनमें से 46,124 नमूनों का विश्लेषण किया गया है और इसे पैंगोलिन वंशावली वर्गीकरण के रूप में निर्धारित किया गया है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सहसंबंध के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को प्रस्तुत किया गया है।

आईएनएसएसीओजी नेटवर्क को 10 प्रयोगशालाओं से 28 प्रयोगशालाओं तक बढ़ाकर जीनोम अनुक्रमण क्षमता को बढ़ाया गया है। अधिक प्रयोगशालाओं को शामिल करके आईएनएसएसीओजी के विस्तार के प्रयास किए गए हैं। एनसीडीसी द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपीएस) को अद्यतन किया जा रहा है ताकि अनुक्रमित किए जाने वाले नमूनों की संख्या के संदर्भ में जीनोम अनुक्रमण की गति में तेजी लाई जा सके और साथ ही अस्पतालों से सीवरेज से नमूनों की रिपोर्टिंग और अनुक्रमण करने और एक समुदाय में फैले कोविड-19 को समझने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण के रूप में निगरानी के लिए समय दिया जा सके।

घ. परीक्षण/निदान

देश भर में सरकारी संस्थानों में कोविड-19 नमूनों के परीक्षण को बढ़ाने के लिए हब और स्पोक मॉडल में शहरी/क्षेत्रीय क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 21 शहरी/क्षेत्रीय क्लस्टर स्थापित किए जा चुके हैं और 55.33 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें से जुलाई 2021 में 4.53 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया था।

ग्रामीण भारत में परीक्षण की पहुंच को और सक्षम बनाने के लिए, कोविड परीक्षण के लिए आई-लैब (संक्रामक रोग प्रयोगशाला) - मोबाइल लैब शुरू की गई। आई-लैब आरटी-पीसीआर और एलिसा दोनों परीक्षण कर सकती है। पहली प्रयोगशाला टीएचएसटीआई हब से जुड़ी है और जुलाई 2021 में इसने लगभग 1,948 परीक्षण किए हैं, जिसे फरीदाबाद क्षेत्र में परीक्षण की संख्या को बढ़ाकर कुल 23,324 तक ले जाना है।

डीबीटी-एएमटीजेड नेशनल कमांड कंसोर्टियम [कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास] भारत में महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की कमी को दूर करने और आत्मनिर्भरता के चरण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय विनिर्माण सुविधा है। एएमटीजेड ने आज तक आरटी-पीसीआर के 575 लाख परीक्षणों (**>10** लाख नैदानिक किट/दिन), **3.5** लाख कोविड-एलिसा परीक्षण, **11** लाख वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, **3000** आईआर थर्मामीटर, **2000** पल्स ऑक्सीमीटर के साथ **4950** वेंटिलेटर और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने में सक्षमता प्राप्त की है।

(ड.) प्रतिरक्षाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई)

विभाग ने वर्तमान स्थिति से संबंधित मुद्दों जैसे भारतीय सीआरओ द्वारा भारत में स्पुतनिक-**v** के उत्पादन और स्पुतनिक की शुरूआत के लिए नियामक मुद्दे; कोविड-19 वैक्सीनों की दो खुराकों के बीच अंतराल की समीक्षा करने; कोविड-19 से पीड़ित पूर्णतया स्वस्थ हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक कोविड-19 खुराक की संख्या; सिंगल आर्म वैक्सीन का प्रभावकारिता परीक्षण; कोविड-19 वैक्सीन विकास और उत्पादन; तथा जेई वैक्सीन उत्पादन आदि पर विचार-विमर्श करने के लिए क्रमश: 03, **09** और 29 जुलाई 2021 को कोवि ड-19 कार्यकारी समूह की 26वीं और 27वीं बैठक और प्रतिरक्षाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की स्थायी तकनीकी उप-समिति की 32वीं बैठक में भाग लिया।

विभाग ने सामान के मुक्त प्रवाह पर चर्चा करने, विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) - विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैक्सीन निर्माताओं के कार्यक्रम को अद्यतन करने के लिए 21 जुलाई 2021 को आयोजित कोवैक्स निर्माण टास्कफोर्स के एसीटी-त्वरित सुविधा परिषद वैक्सीन निर्माण कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। विभाग ने ब्रिक्स देशों के लिए आभासी वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्रों; और आईटी सक्षम वैक्सीन वितरित मंच से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 23 जुलाई को आयोजित "प्रतिरक्षाकरण और कोवि ड -19 वैक्सीन" पर ब्रिक्स की आभासी बैठक में भी भाग लिया।

ii बायोटेक-प्राइड (डाटा विनिमय के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन) दिशानिर्देश

माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई, 2021 को पृथ्वी भवन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली में "बायोटेक-प्राइड दिशानिर्देश" और 'भारतीय जैविक डाटा केंद्र (आईबीडीसी)- राष्ट्रीय भंडार को जैविक डाटा जमा करने के लिए एक वेब पोर्टल' लॉन्च किया।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने व्यापक विशेषज्ञ परामर्श और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के माध्यम से "बायोटेक-प्राइड (डाटा विनिमय के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार का संवर्धन) दिशानिर्देश" जारी किये हैं ताकि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश में उच्च-प्रवाह क्षमता, भारी-मात्रा में जैविक डाटा, ज्ञान और जानकारी साझा करने व उनके आदान-प्रदान को सुगम बनाया जा सके। ये दिशानिर्देश जैविक डाटा के सृजन से संबंधित नहीं हैं, बल्कि देश के मौजूदा कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार सृजित जानकारी और ज्ञान को साझा करने और आदान-प्रदान करने के लिए एक सक्षम तंत्र है। 'बायोटेक-प्राइड दिशा-निर्देश' को तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

iii. <u>जैव सुरक्षा</u>

विभाग ने क्रमशः 19.07.2020 और 22.07.2020 को आनुवंशिक फेरबदल पर समीक्षा समिति (आरसीजीएम) की 210वीं और 211वीं बैठकें आयोजित कीं। बैठकों के दौरान 210वीं आरसीजीएम बैठक में 41 आवेदनों पर विचार किया गया, जबकि 211वीं बैठक में 16 आवेदनों पर विचार किया गया। इन आवेदनों में आयात/निर्यात/स्थानांतरण/प्राप्त, सूचना मदें और बायोफार्मा के लिए पूर्व-नैदानिक विषाक्तता अध्ययन, और कृषि के लिए

आयात/निर्यात/स्थानांतरण/प्राप्त करना शामिल है। प्रत्येक आवेदन पर विचार-विमर्श के बाद आरसीजीएम द्वारा उचित निर्णय लिया गया। माह के दौरान आईबीकेबी पोर्टल पर 16 संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों का गठन किया गया।

iv <u>डीबीटी की सामाजिक पहुंच</u>

क. आजादी का अमृत महोत्सव, भारत*@75*

विभाग जन भागीदारी के आधार पर देश के विभिन्न भागों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। माह के दौरान, विभाग ने "जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता, यात्रा और समाज पर पढ़ने वाले प्रभाव का प्रदर्शन" के बारे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए।

- शोधकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों के बीच सामंजस्य और बातचीत को सुविधाजनक बनाने और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सोच तथा वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रेरित करने के लिए 31 विज्ञान सेतु/ओपन डे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- विभाग के पीएसयू (बीआईआरएसी) द्वारा समर्थित बायोनेस्ट इन्क्यूबेटरों ने मुंबई, पिरावम, चैन्नई और बैंगलोर में कुपोषण के समाधान, मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद, समाज पर बायोटेक का प्रभाव, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे विषयों के तहत 4 सार्वजनिक आउटरीच वेबिनार भी आयोजित किए।
- डीबीटी के स्वायत्तशासी संस्थानों में से एक ने भारतीय विज्ञान की महिमा का जश्न मनाने के लिए प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों डॉ. के.एस. कृष्णन, डॉ. साईकृष्णन कायारत्स, डॉ. जी.एन. रामाचंद्रन और डॉ. सागर सेनगुप्ता के जीवन वृतांत और कार्यों पर चार वेबिनार भी आयोजित किए।
- विभाग के बायोटेक किसान हब ने सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, वैज्ञानिक, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा पशुपालन, कम्पोस्ट खाद के उत्पादन वेज्ञानिक तरीके से जलीय, कृषि, परिपाटियों, संसाधन तथा मूल्यवर्धन और मालभोग केले की उत्पादन प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता तथा मार्गदर्शन कार्यक्रमों को शामिल करते हुए किसान मेलों का आयोजन किया। ये किसान केंद्रित कार्यक्रम ग्रामीण मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे।

v <u>अंतरराष्ट्रीय सहयोग</u>

- इंडो-ऑस्ट्रेलियाई बायोटेक्नोलॉजी निधि: संयुक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आमंत्रण प्रस्ताव (राउंड **14)** 1 जुलाई, **2021** से खोली गई थी। जैवसामग्री (जिनमें बायोप्लास्टिक्स शामिल हैं), डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, कोविड**-19** दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।
- इंडो-फिनिश संयुक्त आमंत्रण प्रस्ताव: अन्वेषक गतिशीलता के लिए वित्तपोषण की घोषणा की गई है। आमंत्रण प्रस्ताव **11** अगस्त, **2021** से **23** सितंबर, **2021** तक

आवेदन पत्र जमा करने के लिए खुला है।

- डब्ल्यूएएच एजेंडा के तहत इंडो डच गोलमेज बैठकें: - बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने क्रमशः 7 और 14 जुलाई, 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ घनिष्ठ साझेदारी में स्वास्थ्य और कृषि पर द्विपक्षीय अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए इंडो डच द्विपक्षीय गोलमेज बैठकें आयोजित की थीं।
- **जैव-ऊर्जा में संभावित द्विपक्षीय सहयोग पर भारत-अमेरिका चर्चा, 21 जुलाई, 2021:** विभाग ने 21 जुलाई, 2021 को आयोजित जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यालय (बीईटीओ), अमेरिकी ऊर्जा विभाग (डीओई) के साथ एक संयुक्त बैठक में भाग लिया। बैठक की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के दूतावास के माध्यम से की गई थी, और बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक से पारंपरिक और उन्नत परिवहन जैव ईंधन के व्यावसायीकरण के द्विपक्षीय अवसरों पर चर्चा हुई।
- 16 जुलाई, 2021 को द नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेजिएट स्कॉलर्स, वाशिंगटन डीसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रौद्योगिकी मानक विकास और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर "राष्ट्रीय महत्वपूर्ण और उभरते प्रौद्योगिकी उपकार्य समूहों" की पहली बैठक में भाग लिया। क्यूयूएडी (क्वाड) देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) के नेताओं ने विश्वसनीय, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी और विविध तकनीकों को मूर्तरूप देने और बढ़ावा देने के लिए सहयोग हेतु विवरण और रोडमैप विकसित करने के लिए 'क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप (सीईटी डब्ल्यूजी)' का गठन किया।
- मिशन नवाचार: एक एकीकृत जैवरिफाइनरी दृष्टिकोण के माध्यम से नवीकरणीय ईंधन रसायन और सामग्री: 27 जुलाई 2021: एक एकीकृत जैवरिफाइनरी दृष्टिकोण के माध्यम से नवीकरणीय ईंधन रसायन और सामग्री पर भारत द्वारा तैयार किए गए मिशन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक आभासी परामर्श बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक का लक्ष्य नए एमआई ढांचे (एमआई 2.0) के तहत एक एकल (स्टैंडअलोन) मिशन के रूप में प्रस्तावित मिशन विषय पर एक स्कोपिंग दस्तावेज़ बनाने के लिए नीदरलैंड से इनपुट, समर्थन और प्रतिबद्धता प्राप्त करनी थी। बैठक में प्रस्तावित मिशन नवीकरणीय ईंधन रसायन और सामग्री के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से डच सहयोगियों से सकारात्मक समर्थन मांगा गया।

Vi प्रकाशन और पेटेंट

माह के दौरान विभाग के स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा 76 शोध प्रकाशन और 01 पेटेंट दायर/प्रदत्त किए गए।

vii एसएएचएजे (सहज) :उपयोग और राजस्व

बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने '**साइंटिफिक इंफास्ट्रक्चर एक्सेस फॉर हार्नेसिंग एकेडेमिया यूनिवर्सिटी रिसर्च ज्वाइंट**' कोलबोरेशन **(सहज)** पोर्टल लांच किया जिसमें डीबीटी-स्वायत्तशासी संस्थानों और डीबीटी समर्थित अवसंरचना कार्यक्रमों में अनुसंधान संस्थानों,

विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टार्ट-अप/उद्यमियों को अपने उपकरण और बुनियादी ढांचे प्रदान करने के साथ-साथ उन्हे साझा भी किया जाता है। माह के दौरान **1,**273 उपयोगकर्ताओं ने डीबीटी स्वायत्तशासी संस्थानों में सेवाओं का लाभ उठाया और कुल 5**,49,**93**,443** /- रूपये का राजस्व अर्जित किया।

viii **बायोटेक्नोलॉजी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान:**
विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान देश में अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे ले जाने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का नेतृत्व कर रहे हैं। अधिक विवरण सलग्नक I पर दिया गया है।

ix **बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) :**
विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) देश में नवाचार, परिवर्तनीय अनुसंधान, उद्योग, स्टार्ट-अप, उद्यमिता और उत्पादन कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अधिक विवरण संलग्नक II पर दिया गया है।

. **महत्वपूर्ण मामलों/मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट**

(i) **दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण लंबित महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: लागू नहीं**

ii) **मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णयों का अनुपालन: लागू नहीं**

अनुपालन के लिए लंबित सीओएस निर्णयों की संख्या	सीओएस निर्णयों के अनुपालन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना/समय-सीमा	अभ्युक्तियां
-	-	-

.ii) **तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' के मामलों की संख्या: शून्य**

iv) **ऐसे मामलों का विवरण जिसमें कार्य के आदान-प्रदान में परिवर्तन हुआ है: शून्य**

(v) **ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति:**

सक्रिय फ़ाइलों की कुल संख्या: 13,766	जुलाई, 2021 के दौरान बनाई गई ई-फाइलों की कुल संख्या-338

vi) **लोक शिकायतों की स्थिति:**

माह के दौरान निवारण की गई लोक शिकायतों की संख्या: 164	माह के अंत में लंबित लोक शिकायतों की संख्या: 17

·ii) **संचालन और विकास में स्थान, तकनीक आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में सूचना: शून्य**

.ii) **क. इस बात की पुष्टि करें कि मंत्रालय/विभाग और उसके संगठनों के ए.सी.सी. के दायरे में आने वाले सभी पदों के कार्यकाल का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है:** यह पुष्टि की जाती है कि विभाग (डीबीटी के अंतर्गत आने वाले सभी स्वायत्तशासी

संस्थानों और उपक्रमों दोनों) में ए.सी.सी. के दायरे में आने वाले सभी पदों का विवरण एवीएमएस पर अद्यतन कर दिया गया है।

ख.एसीसी के निर्देशों के अनुपालन के बारे में स्थिति: उन मामलों के संबंध में एक पैरा जिनमें अलग-अलग शीर्षकों में ए.सी.सी. निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया हैं:यह पुष्टि की जाती है कि ए.सी.सी. के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

ग.उन मामलों की स्थिति, जहां पीईएसबी से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, लेकिन प्रस्ताव अभी एसीसी सचिवालय को प्रस्तुत किए जाने हैं: 'शून्य'

(ix) सरकारी ई-बाज़ार (जीईएम) की स्थिति:

माह के दौरान जीईएम के माध्यम से विभाग द्वारा 4,99,800/-रु. की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की गई है।